



भारत का गज़तापत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167]

नई दिल्ली, सोमवार, प्रप्रैल 20, 1981/बैत्र 30, 1903

No. 167 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1981/CHAITRA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

आरोपण

नई विल्ली, 20 अप्रैल, 1981

का. आ. 305(अ) / 18-च का/आई डी आर ए/81.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (आईयोगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 277(अ) / 18 च का/आई डी आर ए/78, तारीख 20 अप्रैल, 1978 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) बाबारा, केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की भारा 18 च का की उपधारा (1) के सांण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खोलना की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविधानों, संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थाएँनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों और अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो वैकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूतियों में संबंधित है) जिनसे मैमर्स स्वदेशी काटन मिलम कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की (1) मैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी (3) मैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैएनी, (4) मैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथभंजन, (5) मैमर्स उद्योगपुर काटन मिल्स, उदयपुर और (6) मैमर्स रायबरेली टैक्मटाइल्म मिल्स, रायबरेली नामक आईयोगिक उपक्रम पक्षकार हैं या जो ऐसे आईयोगिक उपक्रमों की लागू हो सकती है, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष

की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त सारील से पर्व तदधीन प्रोक्षभूत या उक्षभूत होने वाली सभी वाय्यताएँ और वायित्य उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अस्तित्वाबधि 20 अप्रैल, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उसका आवेदन की अस्सत्वावधि एक वर्ष तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ।

अतः अब, फेन्ड्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की भारा 18 अंश की उपभारा (2) के साथ पठित उपभारा (1) के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त व्यवेश की अस्तित्वान्वित 20 अप्रैल, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बहाती है।

[फा. सं. 3(6)/78-सी. यू. एस.]

आर. एन. चौपडा, भपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1981

S.O. 305(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development, No. S.O. 277(E) 18FB/

IDRA/78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders of other instruments, in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the Industrial undertakings known as (i) M/s. Swadeshi Cotton Mills Kanpur, (ii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) M/s Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) M/s. Rae Bareli Textile Mills, Rae Bareli, of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, are parties or which may be applicable to such industrial undertakings, shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the obligations and liabilities accruing or arising thereunder

before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of said Order was extended upto and inclusive of the 20th April, 1981;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 20th April, 1982.

[File No. 3(6)/78-CUS]
R. N. CHOPRA, Addl. Secy.